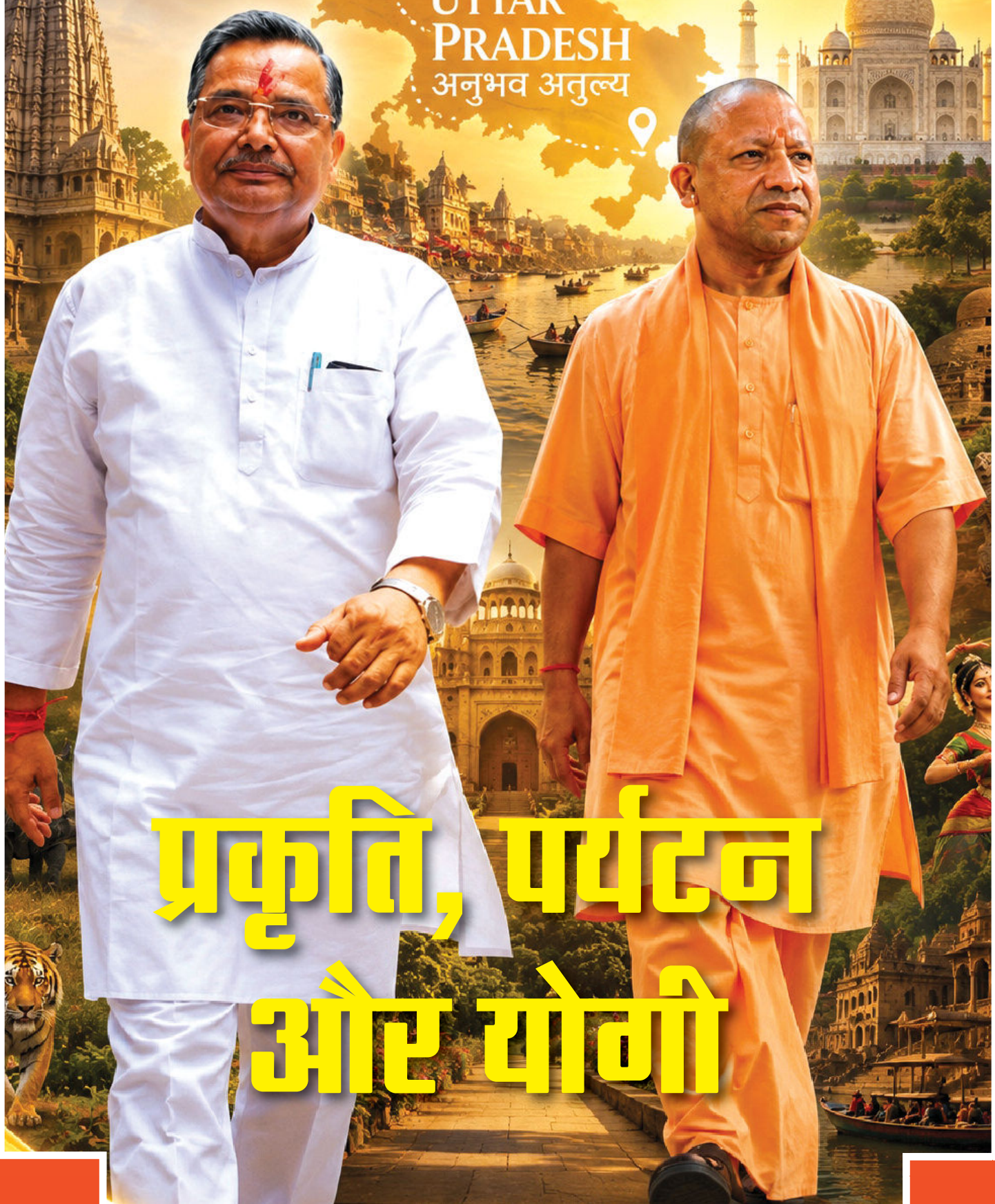
वर्ष : 1 । अंक :11 । जुलाई 2026। पृष्ठ : 36 RNI No. UPHIN/25/A0721 मूल्य : 20

हिन्दी मासिक पत्रिका

पॉलिटिकल इमेज

UTTAR PRADESH
अनुभव अतुल्य



प्रकृति, पर्यटन और योगी

उत्तर प्रदेश सरकार



21% देश के खाद्यान्न उत्पादन में योगदान

गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़कर
₹400 प्रति क्विंटल

यूपी ने करके दिखाया



किसान कल्याण

3.12 करोड़ किसानों को **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** के अंतर्गत **₹1,03,391 करोड़+** की राशि अंतरित

पॉलिटिकल इमेज

वर्ष : 1 । अंक : 11 । जुलाई 2026 । पृष्ठ : 36

संपादक
गरिमा सिंह

स्वामी, प्रकाशक गरिमा सिंह एवं मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41/381 नरही, लखनऊ, ऊ.प्र.-226001 से मुद्रित व सी- 62, इन्दिरा नगर, लखनऊ, ऊ.प्र.-226016 से प्रकाशित।

सम्पादक - गरिमा सिंह

RNI No. UPHIN/25/A0721

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

e-mail
singsgarima@gmail.com

Phone : 8595476939



20 मोदी ने बदली भारतीय...

इस अंक में



प्रकृति, पर्यटन और योगी 80



06 जनसेवा का नया मॉडल



भारत का जल प्रहार 18

संपादक की कलम से...

बदले की भावना



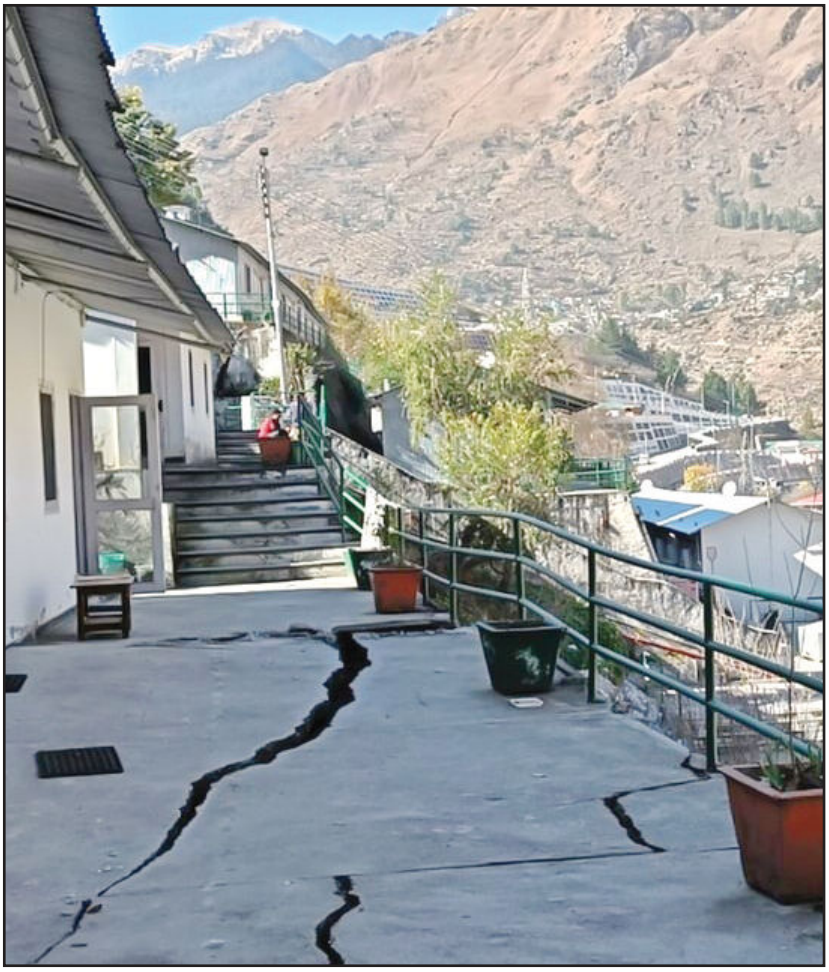
गरिमा सिंह
सम्पादक

पश्चिम एशिया में बदले की भावना के चलते बर्बरता की तमाम हदें कई बार पार हुई हैं। अफसोस, ईरान में फिर यही भावना सिर चढ़कर बोल रही है। ईरान के एक कट्टरपंथी अखबार ने इन्फोग्राफिक प्रकाशित किया है, जिसमें 13 विदेशी नेताओं के नाम हैं। अखबार ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बदले में इन नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। गौर करने की बात है कि ईरानी प्रशासन ने इसका समय रहते खंडन नहीं किया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने 28 फरवरी को पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाते हुए कहा था, 'बदला हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए।' जब किसी देश का सर्वोच्च नेता खुलेआम ऐसा इजहार करेगा, तो देशवासियों में क्या पैगाम जाएगा? ईरान का यह इजहार एक बड़े खतरे की ओर इशारा है।

एक तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता की मर्जी के मुताबिक ही ईरान के इस कट्टरपंथी अखबार ने खतरनाक इरादे से दुनिया को रूबरू कराया है। अब दुनिया में स्वाभाविक ही चिंता की लहर है। जिन नेताओं से ईरान बदला लेना चाहता है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं -डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्जिया मेलोनी, कीर स्टारमर, इमैनुएल मैक्रों, फ्रेडरिक मर्ज इत्यादि। सूची में अमेरिका और इजरायल के नेताओं के नाम नहीं चौंकाते, पर यूरोपीय नेताओं के नाम देखकर चिंता होती है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने ईरान का क्या बिगाड़ा है? दरअसल, ईरान को उम्मीद थी कि इन देशों के नेता ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करेंगे। हालांकि, यूरोप के ये देश ईरान पर हुए हमले के पैरोकार कतई नहीं थे। फिर भी यह तथ्य है कि कुछ यूरोपीय देशों ने अमेरिका को अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया है। यहां ईरान की नाराजगी को समझा जा सकता है, मगर इसका मतलब कतई यह नहीं कि देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निशाना बनाकर बदला लिया जाए। अमेरिका ने जो किया, उसकी निंदा दुनिया के ज्यादातर देश करते हैं। किसी भी देश में घुसकर उसके नेता को निशाना बनाने की अमेरिकी मनमानी की तारीफ कोई नहीं कर सकता, पर जब बदले का फितूर हावी हो जाता है, तब नियम-कायदे और इंसानी तहजीब की बातें किनारे रख दी जाती हैं। बदकिस्मती से ईरान ऐसा ही करता दिख रहा है और यह प्रवृत्ति दुनिया के लिए घातक है।

बदले की ऐसी भावना से ही पश्चिम एशिया में युद्ध फिर भड़क गया है। अमेरिकी भूमि तो ईरान से बहुत दूर है, लेकिन ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ओमान पर हमले करके जवाब दिया है। अमेरिका-इजरायल भी ईरान में बड़े हमले कर रहे हैं। तनाव चरम पर है। होर्मुज जलमार्ग पर यातायात फिर प्रभावित हुआ है। मतलब, दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ना तय है। बहुत मुश्किल से दोनों पक्षों के बीच शांति-वार्ता की स्थिति बनी थी, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। शांति समझौते पर बात चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ता लग रहा है। ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत से भी तनाव बढ़ेगा। अमेरिका में इस मौत की जांच हो रही है कि इसके पीछे ईरान की कोई साजिश तो नहीं है। अब अगर दो-तीन देश ईरान के साथ खुलकर आ गए, तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। दोनों ही तरफ संयम और समझदारी का अभाव साफ दिख रहा है। दुनिया के आम लोग तो यही देखना चाहेंगे कि समाधान या समझौते की कोशिशें कौन शुरू करेगा?

जोशीमठ में भूमि धंसाव को रोकने की कवायद



बारिश का समय आने को है और पर्यावरण को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। ऐसे में, जोशीमठ की नींव को मजबूत करने की कवायद सबका ध्यान खींच रही है। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर को बचाना जरूरी है। उत्तराखंड के हिमालय में 1,875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगभग 25 हजार की आबादी वाला जोशीमठ सामरिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। भारत-चीन सीमा के पास स्थित यह नगर बदरीनाथ धाम, श्री गुरुद्वारा हेमकुण्ड साहिब, औली स्कीइंग स्थल, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क तक पहुंचने का प्रमुख पड़ाव है। ज्योतिर्मठ के नाम से भी चर्चित यह नगर आदि गुरु शंकराचार्य की तपःस्थली है। यह बदरीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल है। बारहमासी तीर्थ यात्रा में भी जोशीमठ की महत्ता है।

लोग भूले नहीं हैं, दिसंबर 2022 में जोशीमठ में कैसे असामान्य भूधंसाव दिखने लगा था, वह दुनिया भर में एक बड़ी खबर थी। सैटेलाइट डाटा के आधार पर बताया गया था कि 2018 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच जोशीमठ में प्रतिवर्ष करीब 10 सेंटीमीटर भूधंसाव हुआ है। वहां चौदह बेहद जोखिम भरे इलाके चिह्नित किए गए थे। उस समय सरकार ने जोशीमठ व राज्य के अन्य शहरों की भी भूमि क्षमता का अध्ययन कराने को कहा था। हालांकि, यह काम अभी तक नहीं हुआ है। निगरानी का भी अभाव देखा जा रहा था। तीन साल बीतने के बाद अब जोशीमठ के स्थिरीकरण का काम हो रहा है। वैसे, जोशीमठ का अगले तीन साल में, यानी 2027 तक स्थिरीकरण का भरोसा अप्रैल 2024 में राज्य के तत्कालीन आपदा प्रबंधन सचिव ने जोशीमठ की जनता को दिया था। जाहिर है, स्थिरीकरण का यह काम भू-वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए।

जीएसआई ने जोशीमठ में 81 दरारों को चिह्नित किया था। इनमें से 42 तो जनवरी 2023 के भूधंसाव के थे। कुछ जगह जल-रिसाव को भी कारण बताया गया था। भूविज्ञानियों के अनुसार, जोशीमठ नगर अतिशय तीखी ढलानों पर बसा है। 1970 के दशक से भूधंसाव को चिह्नित किया जा रहा था। साल 1976 में ही तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त की समिति ने यहां निर्माण नियंत्रण का सुझाव दिया था। उस समिति ने ही बताया था, जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर आधारित नहीं है। इस क्षेत्र में भारी निर्माण पर रोक की सलाह के बावजूद नगर के नीचे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग की परियोजना को 2005 में पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी गई थी। दुर्भाग्य से यह सुरंग साल 2009 में क्षतिग्रस्त हो गई। 'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' का कहना है कि एक तरफ, एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, तो वहीं बाइपास सड़क के लिए जोशीमठ की जड़ पर खुदाई पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। जो भी हो, अप्रैल 2024 के आश्वासन के दो साल बाद अब अप्रैल 2026 में स्थिरीकरण के कार्य की आधिकारिक शुरुआत हुई है। यहां समिति को भरोसे में लेकर चलने की जरूरत है। यहां के लोग जानना चाहते हैं कि स्थिरीकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, वे कितनी सुरक्षा देंगे और कितने स्थायी होंगे?

यहां भूधंसाव को रोकने का कोई भी ठोस व स्थायी प्रयास स्वागतयोग्य है, लेकिन लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है। जो क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां पहले काम करने की जरूरत है। 'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में ही जोशीमठ पर अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट में इस संस्थान ने जो चेतावनी दी थी, उसके प्रति संवेदशील होना जरूरी है। बीते तीन वर्षों में जोशीमठ में क्या बदलाव हुए हैं, इसका गहन अध्ययन जरूरी है। नई समस्या है, यहां भूधंसाव ही नहीं, अब भूफिसलाव भी हो रहा है।

इससे सतही और भूमिगत अस्थिरता आ जाती है। चिंता जताई जा रही है कि जब जोशीमठ की गहराइयों में 80 मीटर तक भी ठोस चट्टान का अता-पता नहीं है, जिसकी भूमि अलकनंदा नदी की ओर खिसक रही है, उसमें दस-बारह मीटर पर रॉक बोल्टिंग्स से स्थिरता कैसे लाई जा सकेगी? जोशीमठ पर पूरे देश की नजर है। इस पुराने नगर को अगर बचाया और फिर बसाया जाता है, तो यह पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: रक्षक ही बने भक्षक

अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर का हालिया घटनाक्रम पुनः राम मंदिर को सुर्खियों में ले आया! मंदिर प्रशासन से जुड़े चंपत राय इन सुर्खियों की जद में आ गये। करोड़ों हिंदुओं की आस्था,लाखों सनातनिओं का दान जिसपर चोरों की नजर लग गई। पहले दान चोरी से हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा था लेकिन अब धीरे धीरे सब उजागर होता जा रहा है,चोरी के धन व सामान की बरामदगी,एफआईआर,इस्तीफ़े इस कहानी और उसके किरदार को बयां कर रहे है जो अभी निरंतर बहस का मुद्दा बना हुआ है।

स्वाभाविक है करोड़ों लोगों की आस्था एवं अटूट विश्वास को धक्का लगना ही था। बात सिर्फ इस पीठ स्थल व श्री राम की पावस नगरी में चोरी की ही नहीं थी बल्कि भगवान के घर चोरी और वो भी तब जब मंदिर बनाने के लिए जाने कितनी कुर्बानियां हर स्तर पर दी जा चुकी थी!अब सवाल चोरी करने वालों पर उठे,उन पर भी उठे जो इन चोरों को खजाने तक लाए थे। इन नामों में सबसे बड़ा नाम चंपत राय बंसल का है। चाहे राम मंदिर आंदोलन का हो या राम मंदिर निर्माण का हो सूत्रो के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के काम से जुड़े चंपत राय के बेहद करीबी लोग ही वो थे जो दान पैसा चुरा रहे थे और छुपा रहे थे, दान को खपा रहे थे, चंपत राय की नाक के नीचे ये काम हो रहा था। सबसे बड़ा और गहरा सवालिया निशान इसी चेहरे पर लगना लाजमी था। चंपत राय पर खुद पैसा चुराने का आरोप नहीं है, लेकिन उनके खास लोगों पर इसका आरोप है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उंगलियां उठीं। उंगलियां उठीं तो चंपत राय की अरसो बनी छवि धूमिल हुई है।

सवाल यह है कि चंपत राय की नाक के नीचे चोरी हुई या उनकी रजामंदी से, चंपत राय चालाकी से केस छुपाना चाहते थे या चोरी सामने आने पर उन्होंने लापरवाही की,राम मंदिर में चोरी की समझने का विषय है.. ज़ब 7 जून को सपा नेता पवन पांडेय ने और 8 जून को अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को उजागर किआ तभी तूल पकड़ा ज़ब की राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग बार बार इंकार करते रहे ये कहके कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव मे अब लड़ाई सत्य हो या असत्य, राजनैतिक होती नजर



आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं जिसका खामियाजा विधान सभा चुनाव 2027 में भुगतना होगा!

जब इस तरह की खबरें आने लगीं तमाम विवाद,आरोप, प्रत्यारोप कि सब कुछ ठीक नहीं है तब इन विषम परिस्थितियो मे प्रदेश सरकार ने 14 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) बना दिया, जो तीन दिन यानी 18 जून तक जांच करती रही। 23 जून को एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट सौप दी, जिसकी 25 जून चढ़ावा चोरी में एफआईआई दर्ज की गई,इस चोरी में केस दर्ज हो गया। जिसमे नाम ऐसे खास लोगों का था जिनसे चंपत जी घिरे रहते थे। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर था। इसके अतिरिक्त अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव हिरासत में लिए जा चुके है जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चंपत राय जी के सिफारिश पर ही राम मंदिर में नौकरी मिली थी जो राम भक्तों से मिलने वाला चंदा गिनने का काम करते थे शायद इसी के नाते चंपत राय विवादों में हैं।

राम मंदिर में दान की चोरी, सिर्फ हाथ की सफाई थी या एक संगठित अपराध ? जांच और राजनीति इसी से सरोबार है...!

बिजनौर के धामपुर में आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर चंपत राय बंसल को 1977 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन तब इमरजेंसी के आंदोलन की वजह से दूसरे संघ कार्यकर्ताओं की तरह 18 महीने जेल में रहे। जब चंपत इमरजेंसी के बाद रिहा हुए विश्व हिदू परिषद में चले गए, जहां वो विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिघल के बेहद करीब आ गए। चंपत को राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए अवध इलाके में युवाओं को तैयार करने का काम दिया गया। चंपत को अयोध्या की हर गली, हर दलील और तारीख मुंह जबानी याद थी और ये तब और अहम हो गया जब मामला तेजी से अदालतों में चलने लगा। वकील तारीखों, और डाटा के लिए चंपत राय की मदद लेने लगे। चंपत को नाम मिल गया, राम लला के रिकॉर्ड कीपर का। बीजेपी ने जब राम मंदिर आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया तो चंपत बीजेपी के नेताओं के करीब आ गए। विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा तो चंपत का नाम साजिशकर्ताओं में शामिल किया गया चंपत अयोध्या के कारसेवक पुरम में ही रह कर ट्रस्ट का काम देख रहे थे। आरोप यह भी है कि इस दौरान उन्होंने अपनी मनमर्जी से लोगों को नौकरियां दीं थी!चंपत ने शुरुआत में ही इस विवाद को दबाने की कोशिश की। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, इन दोनों पार्टियों को राम मंदिर और हिदू राजनीति के मुद्दों पर असहज ही होना पड़ रहा , अब बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी के लिए राम मंदिर आजादी के बाद सबसे सफल आंदोलन रहा, बताते चले बीजेपी के राजनीतिक सफर में इस आंदोलन से ही सत्ता के सफर की बुनियाद पड़ी थी स्वाभाविक है मतदाताओं, राम भक्तों या सनातनियों के दिलो को ठेस लगना सवाल उठाना, लांछन लगाना, जवाब ना मिलना, जिन्होंने तन-मन और धन से बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंपत राय जिस विवाद में पूरी तरह घिर गए हैं। उसकी लपट राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखता है राजनीतिक रूप से धीरे-धीरे ये एक अनौपचारिक गठबंधन जैसा लग रहा है संभवतः सीधे लड़ना बीजेपी के लिए थोड़ा पेचीदा सा लग रहा है। ये ज्वलंत मुद्दा सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर प्रशासन का ही नहीं है, बल्कि करोड़ों हिदुओं की आस्था का सवाल है, ज़ब कि अगली श्रृंखला मे काशी और मथुरा भी शामिल है जिनका भावनात्मक एवं सृजनात्मक सम्बन्ध सनातनियों से जुडा है।चोरी लाखो या करोडो की हो ,सोने की शिलाओं की हो या चांदी के काक भुशुंडी की हो, चोरी तो सिर्फ चोरी ही है। रामलला में करोड़ों की आस्था है इन विषम परिस्थितियो मे चोरी का कलंक धोना आसान नहीं होगा।

आलोक श्रीवास्तव



जनसेवा का नया मॉडल "आपका विधायक-आपके द्वार"

सुशासन, जनकल्याण और संवेदनशील नेतृत्व की मिसाल बने डॉ. राजेश्वर सिंह

लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी मानी जाती है जब जनप्रतिनिधि जनता तक स्वयं पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश की सरोजनीनगर विधानसभा में विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा संचालित "आपका विधायक-आपके द्वार" अभियान इसी सोच का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। लगातार 173 सप्ताह से बिना रुके चल रहा यह अभियान जनसुनवाई को सरकारी दफ्तरों से निकालकर सीधे जनता के बीच ले आया है। यह केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि त्वरित समाधान, जवाबदेही और जनसहभागिता पर आधारित सुशासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुका है।

रविवार को सरोजनीनगर दक्षिण प्रथम मंडल के राजा बिजली पासी द्वितीय वार्ड स्थित शांतिनगर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने स्वयं क्षेत्रवासियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए।

31 जनसमस्याओं के समाधान की पहल

कार्यक्रम के दौरान कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, साइकिल एवं लैपटॉप वितरण, हैंडपंप स्थापना, स्पोर्ट्स किट, मंदिर जीर्णोद्धार, टीन शेड निर्माण, जलभराव, सड़क एवं नाली निर्माण तथा सिलाई मशीन जैसी जनहित से जुड़ी अनेक समस्याएँ शामिल थीं। सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को तत्काल प्रेषित करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि "आपका विधायक-आपके द्वार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की सुविधाओं को जनता के घर तक पहुँचाने का अभियान है। हमारा प्रयास है कि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।"

स्वास्थ्य सेवा: निःशुल्क नेत्र परीक्षण और चश्मों की सौगात

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विजन प्लस के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 लोगों की आँखों की जाँच की गई तथा सभी जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को विधायक की ओर से निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने की घोषणा की गई।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर नेत्र परीक्षण से मोतियाबिंद, ग्लूकोमा तथा दृष्टि संबंधी कई गंभीर समस्याओं की समय रहते पहचान संभव होती है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

युवा शक्ति को खेलों से जोड़ने की पहल

युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से 187वें बॉयज यूथ क्लब तथा 122वें गर्ल्स यूथ क्लब का गठन किया गया। इस अवसर पर बालकों को क्रिकेट एवं वॉलीबॉल किट तथा बालिकाओं को बैडमिंटन, कैरम और वॉलीबॉल किट वितरित की गईं। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित करते हैं। आज जब युवा वर्ग नशे और डिजिटल लत जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब खेल सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं।

मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए महक (77%), आदित्य सिंह (91%), अंशिका व्यास (76.8%) और अदिति सिंह (72.6%) को साइकिल प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा का सम्मान केवल पुरस्कार देना नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। इससे अन्य विद्यार्थी भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं।

माँ तारा शक्ति रसोई: सेवा का विस्तार

कार्यक्रम के दौरान माँ तारा शक्ति निःशुल्क रसोई के माध्यम से क्षेत्रवासियों



एवं जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यह पहल समाज में सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने का संदेश देती है।

डिजिटल सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर युवा

डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरोजनीनगर में संचालित 15 RBS डिजिटल एम्पावरमेंट सेंटर युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन केंद्रों से अब तक 1,001 विद्यार्थी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, जबकि 481 विद्यार्थी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

डिजिटल शिक्षा आज रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। कंप्यूटर कौशल, डिजिटल सेवाओं का ज्ञान तथा ऑनलाइन कार्य संस्कृति युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है।

सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग: खेल के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग के 9 संस्करणों में 10,000 से अधिक युवा भाग ले चुके हैं। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 1,500 से अधिक स्पोर्ट्स किट वितरित की जा चुकी हैं तथा 11 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जा चुकी है। यह लीग युवाओं को नशामुक्त जीवन, अनुशासन, नेतृत्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश देने के साथ-साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है।

प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य नहीं, आत्मविश्वास और नया जीवन

इसी क्रम में विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने लखनऊ गोल्फ क्लब में एसजीपीजीआईएमएस के प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न्स विभाग द्वारा आयोजित विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस जागरूकता वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से जलने की घटनाओं की रोकथाम, सही प्राथमिक उपचार तथा रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के महत्व के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि आम धारणा के विपरीत प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य बढ़ाने की चिकित्सा नहीं है। यह एसिड अटैक पीड़ितों, अग्निदुर्घटना एवं सड़क दुर्घटना के घायलों, जन्मजात विकृतियों से पीड़ित बच्चों, कैंसर के बाद पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले मरीजों तथा गंभीर चोटों से प्रभावित लोगों को नया जीवन, आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करती है।

उन्होंने अपने पुलिस सेवा काल की एक घटना साझा करते हुए कहा

हमने एसिड अटैक के आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाया, लेकिन उसका चेहरा, आत्मविश्वास और जीवन प्लास्टिक सर्जनों ने फिर से संवार दिया। तभी से इस चिकित्सा शाखा के प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ गया।

क्या है रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी ?

रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी शरीर के उन अंगों का पुनर्निर्माण करती है जो दुर्घटना, जलने, कैंसर, जन्मजात विकृति या अन्य कारणों से प्रभावित हो जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल शरीर की बनावट सुधारना नहीं, बल्कि व्यक्ति की कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को पुनः सामान्य बनाना होता है।

राजनीति में जनप्रतिनिधित्व का बदलता स्वरूप

आज जब जनता अपने प्रतिनिधियों से केवल घोषणाएँ नहीं बल्कि परिणाम चाहती है, ऐसे समय में "आपका विधायक–आपके द्वार" जैसी पहल जनप्रतिनिधित्व की नई कार्यशैली प्रस्तुत करती है। नियमित जनसुनवाई, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा प्रोत्साहन, खेल संस्कृति, डिजिटल कौशल विकास और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाला यह मॉडल विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। सुशासन का अर्थ केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, युवाओं का विकास और नागरिकों की गरिमा भी समान रूप से शामिल है। यदि जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें, तो लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होती हैं। सरोजनीनगर में चल रहा यह अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसेवा, जवाबदेही और सहभागी विकास की दिशा में एक सतत प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यही प्रयास भविष्य के विकसित, सक्षम और संवेदनशील भारत की मजबूत आधारशिला सिद्ध हो सकते हैं।



प्रकृति, पर्यटन और योगी

डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध राज्य है। इसलिए यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, इसलिए वह इसे प्रोत्साहित करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय में एक पंथ दो काज किए हैं अर्थात उन्होंने पर्यटन को प्रोत्साहित करके एक ओर राजस्व में वृद्धि करने का कार्य किया है, तो दूसरी ओर इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया है। योगी सरकार ने प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के समक्ष लाने के लिए अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस लेख में प्राकृतिक धरोहरों पर आधारित पर्यटन के विषय में बात की जा रही है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए हैं।

पक्षी अभयारण्य में एआर-वीआर डोम की सुविधा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक एआर-वीआर डोम की सुविधा शीघ्र उपलब्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा यहां कई पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास कराया जा रहा है। इन पर लगभग 2.81 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य के ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर पहली बार आगंतुकों को जंगल का वर्चुअल अनुभव प्राप्त होगा। लखनऊ से लगभग 43 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य प्रमुख रामसर साइट है। पक्षी प्रेमियों, प्रकृति को निकट से अनुभव करने वालों और शहरी भागदौड़ से दूर शांत वातावरण की खोज में जुटे पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण है। शांत, हरेभरे प्राकृतिक वातावरण में स्थित यह सेंचुरी सप्ताहांत पर्यटन के लिए बेहतरीन गतंव्य है। सर्दियों में यहां स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की भारी आमद होती है। उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा यहां एआर-वीआर डोम के साथ-साथ कई अन्य सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है, जिनमें रिसेप्शन/टिकट/वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, फूड एवं ओडीओपी कियोस्क, लैंडस्केपिंग एवं साइट डेवलपमेंट, पौधरोपण, बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज आदि सम्मिलित हैं। एआर-वीआर डोम एक विशिष्ट प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि इसमें जंगल के किसी भी समय की सीन क्रिएट की जा सकती है। सुबह, देर शाम या रात के जंगल का दृश्य, जो अकसर हम नहीं देख पाते हैं, वह हम इस अत्याधुनिक सुविधा के माध्यम से देख सकते हैं। डोम में बैठने के बाद आप चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं। कई जगह तो ऊपर और नीचे का भी दृश्य दिखता है। इस पक्षी अभयारण्य में पर्यटन विकास की





संभावनाओं को साकार करने के लिए बोर्ड सक्रिय है। इसी क्रम में लखनऊ के विविध विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए क्यूरेटेड टूर कराए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से इज माय ट्रिप के साथ एमओयू किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है, जो बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। हमारा लक्ष्य है कि यहां आने वाले पर्यटक अद्वितीय और यादगार अनुभव लेकर लौटें। इसी दिशा में सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए रियायती टूर पैकेज

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली, रोमांच से भरे जंगल सफारी अनुभव और दुर्लभ वन्य जीवों की झलक को अब पर्यटक पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती तरीके से देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रात, दो दिन के पांच विशेष बजट पैकेज तैयार किए हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से तैयार टूर पैकेज पर्यटकों को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को करीब से अनुभव करने का मौका देगा। यह बजट पैकेज उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म, जंगल सफारी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगा। राजधानी लखनऊ के होटल गोमती से 15 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ होने वाले इस टूर पैकेज से संबंधित विशेष जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

लखनऊ-दुधवा यात्रा पैकेज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुविधा है। यात्रा पैकेज में पर्यटकों के ठहरने के लिए जंगल से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर आरामदायक होटल की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रकृति का अनुभव और भी नजदीक से लिया जा सकेगा। यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन, प्रति यात्री दो पानी की बोतल, चाय की चुस्कियों के साथ अलाव का आनंद, अनुभवी गाइड और रोमांच से भरपूर जंगल सफारी भी पैकेज में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव अमृत अभिजात का कहना है कि दुधवा नेशल पार्क के लिए तैयार किए गए ये विशेष बजट राज्य में इको-टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को नई दिशा देंगे। निगम का उद्देश्य है कि पर्यटकों को सुरक्षित और किफायती यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जाए, ताकि परिवार, विद्यार्थी और प्रकृति प्रेमी उत्तर प्रदेश की जैव विविधता को नजदीक से अनुभव कर सकें। दुधवा जैसे प्राकृतिक धरोहर स्थलों के माध्यम से स्थानीय रोजगार, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और सतत पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी।

आगरा के बटेश्वर में नाविक सुनाएंगे लोक कथाएं

यमुना तट पर बसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन ग्राम बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने का महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया है। स्थानीय नाविकों को केवल नाव संचालन तक सीमित न रखते हुए उन्हें कहानी कहने की कला से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे पर्यटकों को बाह बटेश्वर की संस्कृति, इतिहास और आस्था से परिचित कराया जा सके। मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एमकेआईटीएम) लखनऊ के सहयोग से एसडीआरएफ टीम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 7 जनवरी तक नाविकों को आपदा प्रबंधन, आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार तथा ऑनलाइन पेमेंट जैसी आधुनिक सुविधाओं संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार बटेश्वर में ग्रामीण पर्यटन को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। नाविकों को स्टोरी टेलिंग, आपदा प्रबंधन और आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर हम उन्हें केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि बटेश्वर की संस्कृति, इतिहास और आस्था का संवाहक बना रहे हैं। इससे पर्यटकों का अनुभव और अधिक परिपक्व होगा, वहीं स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को हम केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए स्थानीय समुदायों को भी सहभागी बना रहे हैं। नाविकों के निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल, आत्मविश्वास और पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जन सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी को पर्यटन विकास की मजबूत आधारशिला बनाना है, ताकि पर्यटन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

इसके अतिरिक्त कतरनियाघाट एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मूलभूत ढांचा सुधारा गया है। बुंदेलखंड के रानीपुर टाइगर रिजर्व को नए ईको-टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक नीतियां लागू की हैं। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण होटल, रिसॉर्ट एवं होमस्टे बनाने वाले निवेशकों को अनुदान, टैक्स में छूट और आसान ऋण की सुविधा प्राप्त हो रही है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल बनाए गए हैं, जहां बुकिंग, रूट एवं गाइड की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। यहां उन्हें यात्रा से संबंधिक संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।

अयोध्या, वाराणसी एवं आगरा आदि शहरों में स्थानीय लोगों को



अपने घरों को पर्यटकों के लिए होमस्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव प्राप्त होता है और स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है।

पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी पर सराहनीय कार्य किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन शहरों को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विदेशी पर्यटकों के लिए सीधे रास्ते खोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुशीनगर एवं वाराणसी समेत कई घरेलू हवाई अड्डों का विस्तार किया गया है। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे आगरा-मथुरा-काशी-अयोध्या के मध्य पर्यटकों के समय को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मत है कि पर्यटन से केवल एक स्थल विशेष का विकास नहीं होता, अपितु उस क्षेत्र के समग्र विकास एवं ईको-सिस्टम को गति मिलती है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, टैक्सी एवं रेस्टोरेंट आदि क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एवं सुदृढ़ कानून-व्यवस्था भी आवश्यक है। सुरक्षित वातावरण एवं सुगम यात्रा के कारण ही प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आगमन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है।

निःसंदेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आज प्रदेश की आबादी से दोगुनी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हम सभी को नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हम केवल स्थल विशेष का विकास नहीं कर रहे, बल्कि इसके माध्यम से वहां के समग्र विकास, ईको सिस्टम और रोजगार को गति देने का भी काम कर रहे हैं।



आस्था, आरोप और राजनीति के बीच सच की तलाश

अयोध्या केवल एक शहर नहीं है। यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक और नैतिक आदर्श भी हैं। ऐसे में जब राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए, तो यह मामला महज वित्तीय जांच का विषय नहीं रहा। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं, राजनीतिक विमर्श और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।

पिछले कुछ सप्ताहों में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में चढ़ावे में गड़बड़ी हुई? क्या यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप है? क्या दान प्रबंधन प्रणाली में कोई खामी है? या फिर यह मामला आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी संस्थाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता की ओर संकेत करता है?

इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। (The Times of India)

विवाद की शुरुआत कहां से हुई?

मामले की शुरुआत तब हुई जब राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ शिकायतों और राजनीतिक आरोपों में दावा किया गया कि दानपात्रों में जमा होने वाली राशि और उसके आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां हैं।

आरोपों का दायरा बढ़ते-बढ़ते करोड़ों रुपये तक पहुंच गया। कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि भक्तों द्वारा चढ़ाई गई राशि के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि इन आरोपों

की अभी तक जांच एजेंसियों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।

शिकायतों से SIT तक

जैसे-जैसे मामला तूल पकड़ता गया, उत्तर प्रदेश सरकार पर जांच कराने का दबाव बढ़ता गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए जांच कराई जा रही है। एसआईटी को आरोपों की सत्यता, वित्तीय रिकॉर्ड, नकदी प्रबंधन प्रणाली और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच का जिम्मा दिया गया।

SIT किन बिंदुओं की जांच कर रही है?

जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नकदी प्रबंधन प्रक्रिया है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार SIT निम्न बिंदुओं की जांच कर रही है-

- दानपात्रों से नकदी निकालने की प्रक्रिया
- नकदी गिनने की व्यवस्था
- बैंक खातों में राशि जमा होने का रिकॉर्ड
- सीसीटीवी निगरानी
- नियुक्त कर्मचारियों की भूमिका
- दान में मिली बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड
- लेखा परीक्षण और ऑडिट व्यवस्था

इसी क्रम में ट्रस्ट से जुड़े सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से नकदी गिनती व्यवस्था और उससे जुड़े प्रशासनिक निर्णयों पर जानकारी जुटाई।

एफआईआर और शिकायतों की स्थिति

इस पूरे विवाद में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि थाना पहुंचकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ शिकायत दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भक्तों के चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।

हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार जांच अभी जारी है और आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

आम आदमी पार्टी के आरोप

आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम भक्तों द्वारा दिया गया धन सुरक्षित नहीं रहा और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और व्यापक जांच की मांग की।

AAP का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और वित्तीय जवाबदेही दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए।

समाजवादी पार्टी का हमला

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले को लगातार राजनीतिक और नैतिक दोनों मुद्दों के रूप में उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि करोड़ों श्रद्धालुओं का धन गायब हुआ है तो जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस दोषियों तक नहीं पहुंच पाती तो उनकी पार्टी मदद करने को तैयार है। बाद में उन्होंने SIT जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट की सफाई को भी अपर्याप्त बताया।

सपा का तर्क है कि यह मुद्दा भाजपा या विपक्ष का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस विवाद को और आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यदि इतने बड़े स्तर के आरोप लगे हैं तो केवल प्रशासनिक जांच पर्याप्त नहीं है। पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं में आने वाला धन जनता की श्रद्धा का धन है और उसके प्रबंधन पर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।

मंदिर ट्रस्ट का पक्ष

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लगातार यह कहता रहा है कि मंदिर में दान प्रबंधन की एक निर्धारित प्रक्रिया है और आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कहा है कि सभी वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। ट्रस्ट ने यह भी संकेत दिया है कि कई आरोप राजनीतिक प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जांच के बाद ही सामने आएगा।

ट्रस्ट की संरचना और कार्यप्रणाली भी चर्चा में आई है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रस्ट स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और उसकी अपनी वित्तीय एवं ऑडिट प्रणाली है।

योगी सरकार का रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सत्य सामने आने में थोड़ा समय लगेगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं तो उन्हें एसआईटी को सौंपना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अयोध्या और राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

योगी ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि जो दल कभी राम मंदिर आंदोलन के विरोध में खड़े थे, वही आज राम भक्तों की चिंता का दावा कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

इस विवाद की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक याचिका पहुंच चुकी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दान प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि, अभी तक अदालत ने किसी आरोप को सही नहीं माना है और मामला विचाराधीन है।

राजनीति बनाम आस्था

इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यही है। एक पक्ष कहता है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि आस्था जितनी बड़ी होगी, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।

यही कारण है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता के आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता के बड़े प्रश्न को जन्म दिया है।

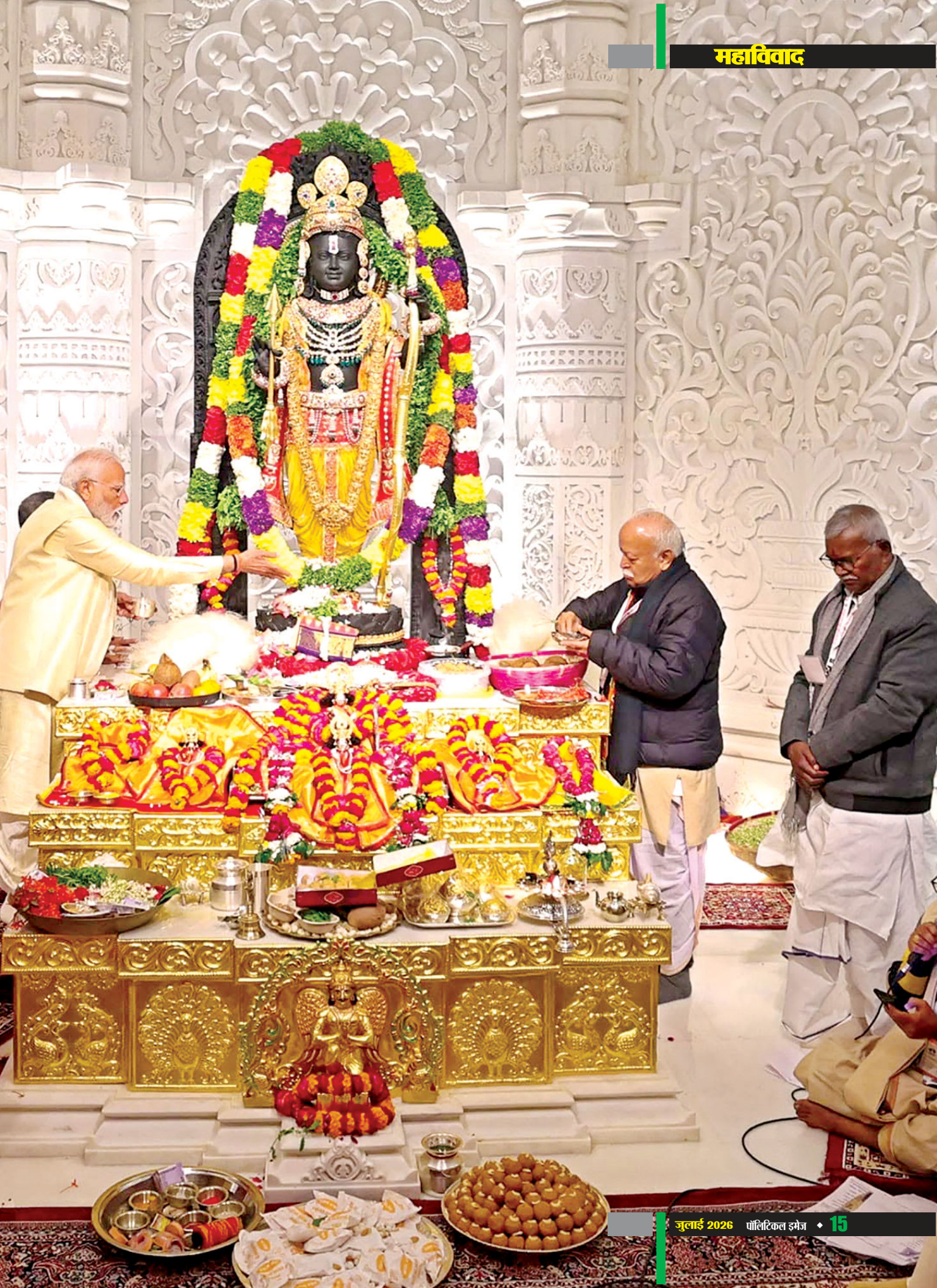
असली सवाल क्या है?

- जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
- लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर देश जानना चाहता है-
- दानपात्रों की निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है?
- नकदी गिनती की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?
- ऑडिट प्रणाली कितनी प्रभावी है?
- बहुमूल्य चढ़ावे का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है?
- क्या भविष्य में ऐसी किसी आशंका को रोकने के लिए अतिरिक्त तकनीकी व्यवस्था की जरूरत है?

राम मंदिर केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होना उतना ही आवश्यक है जितना श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना। आज स्थिति यह है कि आरोप हैं, शिकायतें हैं, राजनीतिक बयान हैं, एसआईटी की जांच है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन अंतिम सत्य अभी सामने आना बाकी है।

देश की नजर अब एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है। यदि आरोप निराधार साबित होते हैं तो इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता मजबूत होगी। यदि कहीं अनियमितता साबित होती है तो कार्रवाई भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए। आस्था और जवाबदेही विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज में एक-दूसरे के पूरक हैं। राम मंदिर विवाद की यह जांच शायद इसी संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है।





बदली रणनीति ! सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर अखिलेश

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पारंपरिक 'सामाजिक न्याय' की राजनीति के साथ अब 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उनके राजनीतिक संदेश, मंदिरों में दर्शन, भगवान श्रीराम और सनातन पर लगातार दिए गए बयान, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर मुखर रुख और धार्मिक आयोजनों में बढ़ती सक्रियता चर्चा में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के साथ बंपर सफलता हासिल की, इसके बाद पार्टी अब इस सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखते हुए हिंदू मतदाताओं के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अब ऐसी राजनीतिक लाइन पर चल रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास है।

मंदिर पर रुख

एक समय भाजपा, सपा पर राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दों से दूरी बनाने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले में अखिलेश लगातार सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, वे अपने बयानों में बार-बार यह भी दोहराते हैं कि 'प्रभु श्रीराम सबके हैं' और हर सनातनी परिवार में रामदरबार की परंपरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 'आस्था और संविधान' दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव और उनके परिवार की धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। वे अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करते दिखाई दिए हैं। कन्नौज में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा भी रहे हैं, जिसकी बात वह हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश के अलावा डिंपल यादव और उनके बच्चे कई मंदिरों में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। हाल में ही अर्जुन और टीना काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। साथ ही सैफई में भंडारा भी आयोजन हुआ। धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सार्वजनिक मंचों से सनातन परंपराओं का जिक्र उनकी नई राजनीतिक शैली का हिस्सा माना जा रहा है।

संतुलन बैठाने की कोशिश

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने पारंपरिक पीडीए वोट बैंक को बनाए रखते हुए हिंदू मतदाताओं के एक हिस्से तक भी पहुंच बनाएं। यही वजह है कि वे एक ओर सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और पिछड़े-दलित अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक आयोजनों, मंदिरों और भगवान श्रीराम से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इस रणनीति का मकसद भाजपा को धार्मिक ध्रुवीकरण का पूरा राजनीतिक लाभ लेने से रोकना भी माना जा रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने 'PDA स्वाभिमान सहयोग अभियान' भी शुरू किया है। इसके तहत QR कोड के माध्यम से न्यूनतम 20 रुपये का सहयोग लेकर पार्टी फंड जुटाने की पहल की गई है। साथ ही डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। पार्टी का दावा है कि यह अभियान केवल चंदा जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और नए समर्थकों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा लंबे समय से 'हार्ड हिंदुत्व' की राजनीति के केंद्र में रही है। राम मंदिर, काशी, मथुरा, सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके प्रमुख मुद्दे रहे हैं। इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी अब सीधे हिंदुत्व का विरोध करने के बजाय धार्मिक आस्था को स्वीकार करते हुए भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उसने आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। यानी अखिलेश यादव का प्रयास यह दिखाने का है कि भगवान श्रीराम सभी के हैं, लेकिन धार्मिक आस्था के नाम पर राजनीति स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की रणनीति कह रहे हैं।

ज्योतिष, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक संदेश

पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंचों पर ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने प्रयागराज में रात्रि विश्राम, मंदिर दर्शन और शुभ-अशुभ संकेतों पर भी बातें की हैं। इन बयानों को भी उनकी बदली हुई राजनीतिक शैली का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से धार्मिक मामले में टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया है, ताकि बीजेपी को बैठे बैठाए कोई मुद्दा न मिल जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी पीडीए सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखते हुए हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग तक पहुंचने में सफल रहती है, तो 2027 का चुनाव भाजपा के लिए पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं, दूसरी राय यह है कि हिंदुत्व के

मुद्दे पर भाजपा की वैचारिक बढ़त अभी भी मजबूत है और केवल धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल से उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा।

2027 की लड़ाई का नया अध्याय

फिलहाल इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहने वाली। एक ओर भाजपा विकास और 'हार्ड हिंदुत्व' के एजेंडे के साथ मैदान में होगी, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए, सामाजिक न्याय और धार्मिक-सांस्कृतिक स्वीकार्यता के कॉकटेल के साथ नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम ही करेंगे।





पाकिस्तान में हाहाकार

भारत का जल प्रहार

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अर्जी लगाई थी उसको यह लगा था कि भारत को दबाव में लाया जा सकता है लेकिन भारत ने अपनी स्थिति बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट कर दी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 6 दशक पुराना सिंधु जल समझौता एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। हाल ही में पाकिस्तान में एक अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस हुई है जिसमें लगातार पाकिस्तान के तमाम राजनेता भारत के खिलाफ इस संधि को लेकर जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के पर्यावरण और जल संसाधन मंत्री मुसद्दीक मलिक ने इसी कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिया है कि जो भी हाथ पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश करेंगे उन हाथों को काट दिया जाएगा, उनका इशारा भारत की तरफ था।

भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम नरसंहार के बाद जून 2025 में स्वयं को 1960 के सिंधु जल समझौते से अलग कर लिया था। हालांकि भारत का यह कहना है कि उसने यह समझौता रद्द नहीं किया है, बल्कि उचित समय तक के लिए इसको स्थगित किया है। भारत अब उस तमाम पानी का जिसको पाकिस्तान उपयोग करता रहा है, इस समझौते के निलंबन के बाद, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। और भारत ने इसके लिए कार्रवाइयां शुरू भी कर दी हैं। समझने की जरूरत है कि भारत इस अतिरिक्त पानी का क्या करेगा जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से पाकिस्तान को जाता रहा है।

भारत ने अपनी मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिया है साथ ही नई जल परियोजनाओं और इससे जुड़े नए ढांचों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को इन नदियों के जल प्रवाह संबंधित डेटा देना बंद कर



दिया है। मौजूदा परियोजनाओं में डी सिल्टिंग/ फ्लशिंग तेज की गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी को रोका जा सके। किश्तवाड़ की मेरुसुदार जैसी नई नई जल विद्युत परियोजनाओं में तेज गति से काम किया जा रहा है। संधि के तहत भारत के हिस्से में आने वाली पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के पानी के समुचित उपयोग के लिए भाखड़ा, पोह, पंडोह, रंजीत सागर, ब्यास सतलज लिंक, इंदिरा नहर आदि परियोजनाओं को और अधिक विस्तृत किया जा रहा है।

साथ ही पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका ज्यादातर अधिकार इस संधि के तहत पाकिस्तान को दिया गया था, के पानी को जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भारत ढांचागत निर्माण पर काम करना शुरू कर चुका है। स्पष्ट कर दें कि संधि के तहत इन पश्चिमी नदियों पर भी पाकिस्तान का पूर्ण स्वामित्व नहीं है, भारत को अपने उपयोग के लिए इन पश्चिमी नदियों को लेकर भी छूट मिली हुई है।

पाकिस्तान में कोलाहल

अब पाकिस्तान में खलबली मचना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पर हाल ही में इसी समझौते को लेकर चल रही डिबेट के दौरान एक विशेषज्ञ ने आंकड़े बताते हुए यह स्वीकारा है कि पिछले 1 साल में ही, जब से भारत ने इस समझौते को निलंबित किया है, पाकिस्तान की तमाम खेती जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है, में करीब 50% की कमी आ चुकी है, सिंध प्रांत में आने वाली खरीफ की फसल की उपज पूरी तरह डांवाडोल दिख रही है। सूखे और बाढ़ के हालातों का सामना करते हुए करीब 6000 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की खेती ही नहीं वहां के उद्योगों को भी जबरदस्त चोट पहुंची है सिर्फ एक इस समझौते के निलंबन की वजह से।

कब तक रहेगा पानी पर पहरा

भारत ने तो स्पष्ट कर दिया था कि वह इस बहुत पुराने समझौते से अपने आप को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से अलग कर रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान को एक सबक होगा। पाकिस्तान जिसके 'क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म' का भारत हमेशा से शिकार रहा है वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसी वजह से पिछले वर्ष जून के महीने में एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया अब इस समझौते के तहत तीनों पश्चिमी नदियों के पानी पर, जिस पर भारत का संधि के तहत बहुत सीमित हक था, उस हक को भारत ने बढ़ाना शुरू किया है। हालांकि यह बड़ी नदियां है और इनको रातों-रात बंद करना असंभव है इस वजह से यह आकलन सही लगता है कि भारत यदि बड़ी तत्परता के साथ भी इन नदियों में नई नई परियोजनाएं बनाएगा तब भी 3 से 10 साल का समय तो लगेगा ही। स्पष्ट है कि संधि का निलंबन बहुत लंबा चलने वाला है। भारत की कोशिश रहेगी कि इन तमाम नदियों का पानी वह अपने मैदानी और सूखा प्रभावित जिलों, प्रदेशों की तरफ ले जाए जिससे कि यहां कृषि क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सके। पाकिस्तान के लिए एक दंड है और पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो यह दंड लगातार जारी रहेगा।

इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम संधियों में से कुछ ही संध्या ऐसी हैं जो कि इतने लंबे समय तक टिकी रही हैं। एक स्थाई समाधान जैसा व्यवहार भारत और पाकिस्तान दोनों ने अब तक किया था। हालांकि यहाँ भारत की बड़ी भूमिका थी क्योंकि यह तमाम नदियां, जो कि बाद में पाकिस्तान में जाती है, भारत से ही निकलती हैं। और भारत जब चाहता तब इनके पानी को रोक सकता था। फिर भी तीन-तीन युद्ध देखने के बाद भी भारत ने इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम हमेशा से यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं।

पाकिस्तान की उलझने बढ़ेंगी

पाकिस्तान जो कि आतंक का बहुत बड़ा गढ़ है वह भारत से इतने सख्त रुख की आशा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान को विश्वास था कि अंतरराष्ट्रीय दबावों का इस्तेमाल करके वह भारत को इस मसले पर झुका ले जाएगा। पाकिस्तान को यह भी लगता था कि पहलगाम घटना के बाद जिस तरह से भारत के अंदर पाकिस्तान के प्रति एक रोष दिखाई दिया था, भारत सरकार इस समझौते के निलंबन के माध्यम से कुछ हद तक उसे कम करना चाहती है और बाद में यह समझौता फिर से वापस पटरी पर आ जाएगा।

पाकिस्तान के अंदर आज दो तरह की आवाजें हैं एक शुद्ध राजनीतिक है और दूसरी वहां के नागरिकों की आवाज। राजनीतिक आवाज पुरजोर भारत विरोध की है क्योंकि उनको अपनी खामियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान सिर्फ अपने नागरिकों के मनोभावों को भड़काना चाहते हैं। भारत विरोध का माहौल और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। रही बात नागरिकों की तो वह लगातार अपनी परेशानियों, महंगाई, राशन और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उनकी खेती बर्बाद हो रही है। परिस्थितियां इस कदर भयानक होती जा रही है कि आने वाले समय में वहां के जिलों के बीच और सूबों के बीच में आपस में युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत के अकाट्य तर्क और कूटनीति

तो अब पाकिस्तान के पास भारत के इस दांव का उपचार क्या है? पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अर्जी लगाई थी उसको यह लगा था कि भारत को दबाव में लाया जा सकता है लेकिन भारत ने अपनी स्थिति बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट कर दी है। यह बता दिया गया है कि भारत फिलहाल यह कदम संधि के अनुरूप ही उठा रहा है। संधि में इस तरह के प्रावधान थे कि विशेष परिस्थितियों में इस संधि पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

सिंधु जल संधि के आर्टिकल 12 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी पक्ष एक तरफा इस समझौते से खुद को अलग नहीं कर सकता है और विश्व बैंक ने इस बात की गारंटी भी दी थी। लेकिन विश्व बैंक यहां पर एक पार्टी नहीं था वह सिर्फ फैसिलिटेटर था जिसने यह बैठक आयोजित करवाई थी। 1960 में पाकिस्तान इस चीज को समझ ही नहीं पाया था और भारत के शांतिपूर्ण रवैये को भारत की कमजोरी मान बैठा था। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भारत ने स्पष्ट किया है कि संधि में यह लिखा हुआ है की विशेष परिस्थितियों में, जो कि भविष्य में आ सकती हैं, इस संधि को पुनः रैटीफाई किया जा सकता है। भारत के लिए तो विशेष स्थिति चल ही रही है। बार-बार कहने के बावजूद पाकिस्तान अपनी जमीन का उपयोग आतंक फैलाने के लिए करता रहा है। भारत बहुत बर्दाश्त कर चुका है। अब भारत इस संधि पर पुनर्विचार कर रहा है और पुनर्विचार करने के लिए ही उसने इस संधि को फिलहाल निलंबित करके रखा हुआ है। भारत के इस तर्क का अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में किसी भी पक्षकार के पास कोई जवाब नहीं था। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव का भारत के ऊपर कोई फर्क फिलहाल पड़ता नहीं दिख रहा है।



मोदी ने बदली भारतीय राजनीति की धारा और दिशा

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ ऐसे दौर आते हैं, जो केवल सरकारों के कार्यकाल नहीं होते, बल्कि एक युग के रूप में याद किए जाते हैं। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली थी, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि अगले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और शासन व्यवस्था में इतने व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जून 2026 में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह अवसर केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक यात्रा का मूल्यांकन करने का भी है जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। नरेन्द्र मोदी आज केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक घटना बन चुके हैं, जिनके प्रभाव को नकारना उनके आलोचकों के लिए भी संभव नहीं है। 2014 से 2026 तक का यह सफर अनेक उपलब्धियों, चुनौतियों, विवादों, प्रयोगों और ऐतिहासिक निर्णयों से भरा रहा है।

2014: बदलाव की उम्मीद से शुरू हुई यात्रा

वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ था। लंबे समय तक गठबंधन राजनीति और नीति-निर्णयों में सुस्ती के आरोपों के बीच जनता एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में थी। गुजरात मॉडल, विकास के एजेंडे और प्रभावशाली संवाद शैली के दम पर नरेन्द्र मोदी ने देशभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन हासिल किया।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगभग तीन दशक बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व-केंद्रित राजनीति के नए दौर की शुरुआत थी।

जनधन से डिजिटल इंडिया तक: वित्तीय समावेशन की नई कहानी

मोदी सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं में वित्तीय समावेशन प्रमुख था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। ऐसे परिवार, जिनके पास कभी बैंक खाता नहीं था, वे औपचारिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बने।

जनधन खाते, आधार और मोबाइल के त्रिकोण- जिसे 'जैम ट्रिनिटी' कहा गया, ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाई। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगे।

इसी अवधि में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, जिसने देश में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को नई गति दी। आज यूपीआई दुनिया में डिजिटल भुगतान के सबसे सफल मॉडलों में गिना जाता है।

स्वच्छ भारत: जनभागीदारी का बड़ा अभियान

2 अक्टूबर, 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं था, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। देशभर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ और खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

हालांकि इस अभियान की प्रभावशीलता और स्थायित्व को लेकर बहस होती रही, लेकिन यह निर्विवाद है कि स्वच्छता का मुद्दा पहली बार राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आया।

नोटबंदी: सबसे बड़ा और सबसे विवादित फैसला

8 नवंबर, 2016 भारतीय आर्थिक इतिहास की सबसे चर्चित तारीखों में से एक है। इसी दिन सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इसे काले धन, जाली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर प्रहार बताया, जबकि आलोचकों ने इसे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कदम माना।

नोटबंदी आज भी राजनीतिक और आर्थिक बहस का विषय बनी हुई है। यह निर्णय मोदी सरकार की कार्यशैली को भी परिभाषित करता है- बड़े और साहसिक फैसले लेने की प्रवृत्ति, चाहे उनके परिणामों पर मतभेद क्यों न हों।

जीएसटी: एक देश, एक कर

वर्ष 2017 में लागू हुआ गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक माना जाता है। इससे पहले देश में अलग-अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लागू थे। जीएसटी ने पूरे देश को एक साझा कर व्यवस्था में बांधने का प्रयास किया। शुरुआती चुनौतियों और तकनीकी समस्याओं के बावजूद यह व्यवस्था धीरे-धीरे स्थिर हुई और कर संग्रह में वृद्धि देखने को मिली।

राष्ट्रीय सुरक्षा: आक्रामक नीति का संदेश

मोदी सरकार के 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख प्रमुख पहचान बनकर उभरा। वर्ष 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने सरकार की सुरक्षा नीति को नई पहचान दी।

इन कार्रवाइयों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मोदी सरकार की राजनीतिक ताकत का भी एक प्रमुख आधार बना।

अनुच्छेद 370: सात दशक पुराना अध्याय समाप्त

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और बहुचर्चित निर्णय लेते हुए आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। दशकों से भाजपा के वैचारिक एजेंडे में शामिल यह मुद्दा आखिरकार साकार हुआ।

सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि

विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों ने इसके राजनीतिक और संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाए। फिर भी यह निर्णय मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों में गिना जाता है।

राम मंदिर: लंबे संघर्ष का परिणाम

भारतीय राजनीति में शायद ही कोई मुद्दा राम मंदिर जितना लंबे समय तक चर्चा में रहा हो। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठापन के साथ दशकों पुराना विवाद एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा और उसके समर्थकों के लिए वैचारिक उपलब्धि के रूप में देखा गया। इस घटना ने भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक विमर्श दोनों को प्रभावित किया।

कोरोना महामारी: सबसे कठिन परीक्षा

वर्ष 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और आर्थिक चुनौतियां सरकार के सामने बड़ी परीक्षा थीं।

दूसरी ओर, देशव्यापी टीकाकरण अभियान को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रमों में शामिल किया गया। महामारी के दौरान सरकार की नीतियों की सराहना भी हुई और आलोचना भी। मगर, यह दौर मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में याद किया जाएगा।

विदेश नीति: वैश्विक मंच पर बढ़ती उपस्थिति

मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय और दृश्यमान दिखाई दी। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जापान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जी-20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने देश की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया। आज भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज और उभरती महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार

मोदी सरकार ने गरीब, किसान, महिला और ग्रामीण परिवारों को केंद्र में रखकर कई योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया। इन योजनाओं ने सरकार को ग्रामीण और निम्न





आय वर्ग में मजबूत राजनीतिक आधार प्रदान किया।

आत्मनिर्भर भारत और विनिर्माण पर जोर

कोरोना महामारी के बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, रक्षा उत्पादन बढ़ाने और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। 'मेक इन इंडिया' और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की कोशिश जारी है।

आलोचनाएं और चुनौतियां भी कम नहीं

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की तरह मोदी सरकार भी आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न और संस्थागत स्वायत्तता पर उठे सवाल विपक्ष और आलोचकों के प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे आंदोलन के बाद सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा। यह घटना बताती है कि जनमत का दबाव लोकतंत्र में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनावी राजनीति का नया अध्याय

मोदी युग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक भाजपा का लगातार विस्तार रहा है। पार्टी ने कई राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत की और राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाया। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी रणनीति ने भाजपा को लगातार चुनावी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व आधारित चुनावी मॉडल को मजबूती मिली।

12 वर्षों का निष्कर्ष

नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों का मूल्यांकन केवल समर्थकों या विरोधियों के नजरिए से नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा दौर रहा है जिसमें बड़े फैसले लिए गए, शासन की कार्यशैली बदली, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हुआ, डिजिटल क्रांति को गति मिली और भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत हुई।

साथ ही यह भी सच है कि रोजगार, सामाजिक समरसता, कृषि और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी देश के सामने मौजूद हैं। किसी भी लोकतांत्रिक नेतृत्व की तरह मोदी सरकार की उपलब्धियों और कमियों दोनों पर चर्चा होती रहेगी।

लेकिन इतना निश्चित है कि 2014 से 2026 तक का यह कालखंड भारतीय राजनीति के इतिहास में ₹मोदी युग₹ के रूप में दर्ज हो चुका है। आने वाले वर्षों में इतिहासकार जब इस दौर का मूल्यांकन करेंगे, तो वे इसे केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखेंगे।

बारह वर्षों की इस यात्रा ने यह स्थापित कर दिया है कि नरेन्द्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि समकालीन भारत की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले नेताओं में से एक हैं।





राजस्थान में 13 जिलों की प्यास बुझाने का मिशन

मोदी-भजनलाल की जुगलबंदी और 2027 तक टैंकर मुक्त राजस्थान

राजस्थान का नाम लेते ही तपती रेत, कम वर्षा और पानी के संकट की तस्वीर सामने आती है। देश के सबसे बड़े भौगोलिक राज्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा वर्षों से जल संकट से जूझता रहा है। गर्मियों में पेयजल के लिए लंबी कतारें, टैंकरों पर निर्भर गांव और सिंचाई के लिए संघर्ष यहां की पहचान बन गए थे। लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल तेजी से आगे बढ़ रही है—ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट।

कभी राजनीतिक विवादों में उलझी यह परियोजना आज केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से जमीन पर गति पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने इसे प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल किया है। वर्ष 2025-26 के बजट में लगभग 9,600 करोड़ का प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार इसे केवल जल परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वी राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक बदलाव के मिशन के रूप में देख रही है।

यदि निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्य पूरा होता है तो वर्ष 2027 तक पूर्वी राजस्थान के लाखों परिवारों को टैंकरों पर निर्भरता से राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या है ERCP ?

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त वर्षाजल का वैज्ञानिक उपयोग करते हुए जल संकट वाले क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना है।

परियोजना के तहत बांधों, बैराजों, पंपिंग स्टेशनों, विशाल पाइपलाइन नेटवर्क और नहर प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

यह परियोजना केवल पानी पहुंचाने का काम नहीं करेगी बल्कि जल प्रबंधन की आधुनिक प्रणाली विकसित करेगी।

13 जिलों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ

ERCP का सबसे अधिक लाभ पूर्वी राजस्थान के उन जिलों को मिलेगा जहां वर्षों से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है।

इन जिलों में प्रमुख रूप से—

- जयपुर
- अजमेर
- दौसा
- अलवर
- भरतपुर
- धौलपुर
- करौली
- सवाई माधोपुर



- टोंक
- बूंदी
- कोटा
- बारां
- झालावाड़

जैसे जिले शामिल हैं।

इन क्षेत्रों की बड़ी आबादी को भविष्य में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

मोदी–भजनलाल की जुगलबंदी से मिली नई रफ्तार

ERCP लंबे समय तक केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा का विषय रहा। लेकिन वर्तमान में केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से परियोजना को नई गति मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल सुरक्षा को विकसित भारत की आधारभूत आवश्यकता बताया है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के भविष्य का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन माना है।

दोनों सरकारों के समन्वय से—

वित्तीय स्वीकृतियां तेज हुईं।

तकनीकी बाधाओं का समाधान हुआ।

परियोजना की विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत हुआ।

निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग शुरू हुई।

9,600 करोड़ का बजट क्यों महत्वपूर्ण है?

इतनी बड़ी राशि का प्रावधान केवल निर्माण कार्य के लिए नहीं बल्कि परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की प्रतिबद्धता का संकेत भी है।

इस बजट से—

- नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
- पंपिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं।
- जलाशयों का विस्तार हो रहा है।
- वितरण नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
- आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

पाइपलाइन का काम कहां तक पहुंचा?

परियोजना के तहत कई हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने, जल संरचनाओं के निर्माण तथा पंपिंग स्टेशनों का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है।

जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है वहां निर्माण कार्य अपेक्षाकृत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कई पैकेजों में ठेकेदार एजेंसियां चौबीसों घंटे कार्य कर रही हैं।

सरकार ने परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी बनाई है ताकि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा किया जा सके।

टैंकर मुक्त राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम

राजस्थान के अनेक गांवों में हर गर्मी के मौसम में पेयजल टैंकर भेजने पड़ते हैं।

टैंकर व्यवस्था आपातकालीन समाधान तो है लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं।

ERCP के पूरा होने के बाद—

- नियमित पेयजल आपूर्ति संभव होगी।
- टैंकरों पर खर्च कम होगा।
- जल वितरण अधिक व्यवस्थित होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम होगा।
- यदि योजना निर्धारित गति से आगे बढ़ती है तो 2027 तक कई क्षेत्रों में टैंकर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

किसानों के लिए नई उम्मीद

- पूर्वी राजस्थान के किसान वर्षों से वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहे हैं।
- परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा बढ़ने पर—
- फसल विविधीकरण संभव होगा।
- उत्पादन बढ़ेगा।
- नकदी फसलों का विस्तार होगा।
- कृषि आय में वृद्धि की संभावना बनेगी।
- सिंचाई उपलब्ध होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया आधार मिलेगा।

उद्योगों को भी मिलेगा लाभ

- जल उपलब्धता किसी भी औद्योगिक निवेश का महत्वपूर्ण आधार होती है।

ERCP के माध्यम से—

- औद्योगिक क्षेत्रों में जल आपूर्ति बेहतर होगी।
- नए निवेश आकर्षित होंगे।
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- शहरों की बढ़ती आबादी के लिए राहत
- जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई शहर तेजी से विस्तार कर रहे हैं।
- बढ़ती आबादी के कारण भविष्य की जल आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है।
- ERCP शहरी जल प्रबंधन की दीर्घकालिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

भूजल संरक्षण में भी सहायक

राजस्थान में लगातार गिरता भूजल स्तर बड़ी चिंता का विषय रहा है।

- जब सतही जल की उपलब्धता बढ़ेगी तो—
- ट्यूबवेल पर निर्भरता घटेगी।
- भूजल दोहन कम होगा।
- जल पुनर्भरण की स्थिति बेहतर होगी।
- पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा।

रोजगार का भी बड़ा स्रोत

इतनी विशाल परियोजना हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न कर रही है।

निर्माण कार्यों में—

- इंजीनियर
- तकनीकी विशेषज्ञ
- मशीन ऑपरेटर
- श्रमिक

परिवहन क्षेत्र

- सभी को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है।
- चुनौतियां भी कम नहीं
- इतनी बड़ी परियोजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं—
- भूमि अधिग्रहण
- पर्यावरणीय स्वीकृतियां
- समयबद्ध निर्माण
- लागत नियंत्रण

विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय

सरकार का दावा है कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

जल सुरक्षा से विकास तक

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जल ही सबसे बड़ा विकास संसाधन होगा।

ERCP केवल पानी पहुंचाने की योजना नहीं बल्कि—

- स्वास्थ्य सुधार,
- कृषि विकास,
- औद्योगिक निवेश,
- महिला सशक्तिकरण,
- ग्रामीण विकास का भी आधार बनेगी।

2027 : क्या बदल जाएगी तस्वीर ?

यदि परियोजना निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो वर्ष 2027 तक पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्से में जल संकट की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।

सरकार का लक्ष्य है कि—

- पेयजल की उपलब्धता बेहतर हो।
- टैंकरों की आवश्यकता न्यूनतम रह जाए।
- सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हो।
- जल प्रबंधन आधुनिक बने।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को स्थायी जल समाधान मिले।

बेहतर उम्मीद कायम :

ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट केवल एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं, बल्कि राजस्थान के जल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने की क्षमता रखता है। वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहे पूर्वी राजस्थान के लिए यह योजना नई उम्मीद लेकर आई है। 9,600 करोड़ के बजटीय प्रावधान, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास तथा तेज़ी से चल रहे निर्माण कार्य इस महत्वाकांक्षी मिशन को गति दे रहे हैं।

हालांकि किसी भी विशाल अवसंरचना परियोजना की सफलता उसके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूरा होता है, तो वर्ष 2027 तक राजस्थान के लाखों लोगों को स्थायी पेयजल उपलब्ध कराने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और टैंकर निर्भरता कम करने की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। यही कारण है कि ERCP को आज केवल जल परियोजना नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है।

ERCP एक नजर में

- परियोजनाः ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP)
- मुख्य उद्देश्यः पेयजल, सिंचाई और जल सुरक्षा
- लाभार्थीः पूर्वी राजस्थान के 13 जिले
- बजट प्रावधानः लगभग 9,600 करोड़
- प्रमुख लक्ष्यः 2027 तक जल संकट में उल्लेखनीय कमी और टैंकर निर्भरता घटाना
- मुख्य लाभः पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक विकास, भूजल संरक्षण और रोजगार सृजन

डिजिटल यूपी

गांव तक पहुंचती तकनीक, बदलती तस्वीर

स्मार्ट प्रशासन और साइबर जागरूकता से सशक्त हो रहा ग्रामीण उत्तर प्रदेश



भारत में डिजिटल क्रांति का सबसे प्रभावी असर अब गांवों में दिखाई देने लगा है। कभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तहसीलों और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने वाले ग्रामीण आज अपने गांव में ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीक पहुंचाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। परिणामस्वरूप गांवों में प्रशासनिक सेवाएं तेज, पारदर्शी और अधिक जवाबदेह हुई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक आधारित सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, ई-ऑफिस, ऑनलाइन ग्राम सचिवालय, साइबर सुरक्षा जागरूकता और इंटरनेट आधारित सेवाओं ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है।

गांव-गांव पहुंचा डिजिटल प्रशासन:

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाएं उनके घर के निकट उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाया है। आज अधिकांश ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था विकसित की जा रही है। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र, पेंशन आवेदन, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, मनरेगा भुगतान जैसी अनेक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों बच रहा है तथा सरकारी कार्यालयों पर निर्भरता भी कम हुई है।

ऑनलाइन ग्राम सचिवालय :

- गांव में ही सरकारी कार्यालय
- प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल ऑनलाइन ग्राम सचिवालय ग्रामीण प्रशासन में बड़ा बदलाव लेकर आई है।
- अब पंचायत सचिवालय केवल कागजी रिकॉर्ड रखने का स्थान नहीं रह गया है बल्कि डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।
- ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी, आवेदन, प्रमाणपत्र, शिकायत पंजीकरण तथा सरकारी पोर्टलों तक पहुंच गांव में ही मिलने लगी है।
- इससे पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच रहा है।

डिजिटल भुगतान ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- कुछ वर्ष पहले तक गांवों में अधिकांश लेन-देन नकद होता था।

आज स्थिति तेजी से बदल रही है।

- यूपीआई, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
- सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है तथा पारदर्शिता बढ़ी है।
- मनरेगा मजदूरी, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुंचने से ग्रामीणों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत हुआ है।

महिलाएं भी बन रही हैं डिजिटल सशक्त :

- डिजिटल तकनीक का सबसे सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर दिखाई दे रहा है।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं मोबाइल के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं तथा अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर रही हैं।
- डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाया है।

कृषि में भी बढ़ रही तकनीक की भूमिका

- डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहे हैं।
- किसान मौसम की जानकारी, मंडी भाव, फसल बीमा, कृषि सलाह, उर्वरक एवं बीज संबंधी जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण, ई-नाम जैसी व्यवस्थाओं और डिजिटल भुगतान से कृषि क्षेत्र में भी पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।

स्मार्ट प्रशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश :

- प्रदेश सरकार ने ई-ऑफिस, ऑनलाइन फाइल प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को तेजी से लागू किया है।
- इससे सरकारी कार्यों की गति बढ़ी है, जवाबदेही मजबूत हुई है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनी है।
- शिकायत निवारण पोर्टल, ऑनलाइन जनसुनवाई तथा डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से आम नागरिक सीधे शासन से जुड़ रहे हैं।

साइबर जागरूकता की बढ़ती जरूरत :

- डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ा है।
- सरकार और पुलिस विभाग लगातार साइबर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोग ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयर करने, नकली लिंक और साइबर फ्रॉड से बच सकें।
- विद्यालयों, कॉलेजों, पंचायतों तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल विकास तभी सफल होगा जब उसके साथ साइबर सुरक्षा की समझ भी समान रूप से विकसित हो।

इंटरनेट बना ग्रामीण विकास की नई ताकत :

- भारतनेट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रोजगार और सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है।
- ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी पोर्टलों का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

युवाओं के लिए खुले नए अवसर

- डिजिटल क्रांति ने गांवों के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), ऑनलाइन सेवा केंद्र, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवा अपनी पहचान बना रहे हैं।
- तकनीकी कौशल विकसित होने से स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

अभी भी मौजूद हैं कुछ चुनौतियां

- हालांकि डिजिटल परिवर्तन तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं—
- कुछ गांवों में इंटरनेट की गुणवत्ता अभी भी संतोषजनक नहीं है।
- डिजिटल साक्षरता का स्तर सभी आयु वर्ग में समान नहीं है।
- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है।
- बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे लोगों को डिजिटल सेवाओं के उपयोग में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
- इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार और समाज दोनों की साझी भागीदारी आवश्यक है।

नई पहचान :

उत्तर प्रदेश में डिजिटल तकनीक अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों के विकास की नई पहचान बन रही है। ऑनलाइन ग्राम सचिवालय, डिजिटल भुगतान, स्मार्ट प्रशासन, ई-गवर्नेंस, साइबर जागरूकता और इंटरनेट आधारित सेवाओं ने ग्रामीण जीवन को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार डिजिटल उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा को समान गति से आगे बढ़ाया जाता रहा, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र तकनीक आधारित विकास का एक सशक्त मॉडल बनकर उभरेगा।

डिजिटल गांव की पांच बड़ी उपलब्धियां –

- ऑनलाइन ग्राम सचिवालय की सुविधा
- यूपीआई और डिजिटल भुगतान का विस्तार
- सरकारी योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान
- पंचायतों में डिजिटल रिकॉर्ड और ई-गवर्नेंस
- साइबर जागरूकता अभियान का विस्तार

गांवों में डिजिटल बदलाव के प्रमुख लाभ –

- सरकारी सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध
- भ्रष्टाचार और बिचौलियों में कमी
- समय और धन की बचत
- पारदर्शी प्रशासन
- महिलाओं और युवाओं का डिजिटल सशक्तिकरण

ईरान का कृत्रिम मस्तिष्क

प्रतिबंधों की छाया में वैज्ञानिक प्रकाश

जब दुनिया के सबसे कठोर प्रतिबंधों ने एक देश को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से काट दिया, तब उस प्राचीन सभ्यता ने अपने भीतर झांका। तेहरान की प्रयोगशाला में विकसित 'जीवित न्यूरॉन्स' से बना कृत्रिम मस्तिष्क केवल एक तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक बाधाओं के विरुद्ध विज्ञान की अदम्य इच्छाशक्ति का सजीव प्रमाण है।

जब इच्छाशक्ति विज्ञान बन जाए

तेहरान की एक अत्याधुनिक, उच्च-सुरक्षा वाली प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जो विज्ञान, दर्शन और तकनीक के बीच की सारी पारंपरिक सीमाओं को धुंधला कर रहा है। एक विशेष पोषक तरल (न्यूट्रिएंट मीडियम) में लाखों जीवित मानव न्यूरॉन तैर रहे हैं। ये कोई साधारण मृत या निष्क्रिय कोशिकाएं नहीं हैं, ये स्वतः ही एक-दूसरे से जुड़ रही हैं, सिनैप्स (Synapses) का निर्माण कर रही हैं, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से, बाहरी डेटा को 'सीख' रही हैं। यह किसी हॉलीवुड विज्ञान कथा (Sci-Fi) फिल्म का दृश्य नहीं है; यह वर्तमान ईरान



की नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धि का सजीव चित्र है, एक कृत्रिम मस्तिष्क जो जीवित मानव कोशिकाओं से निर्मित है।

27 जून, 2026 को ईरान के 'संज्ञानात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यबल' के सचिव डॉ. अताउल्लाह पौर-अब्बासी ने मेहर समाचार एजेंसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इस ऐतिहासिक सफलता की घोषणा की। उनके शब्दों में, ईरान ने शरीर के बाहर तंत्रिका कोशिकाओं को संवर्धित करने की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जो सिनैप्टिक कनेक्शन स्थापित करने और सीखने में सक्षम जैविक नेटवर्क बनाने की क्षमता रखती हैं। यह मात्र एक प्रयोगशाला का सफल प्रयोग नहीं है। यह पिछले लगभग पचास वर्षों से लगातार आर्थिक, कूटनीतिक और तकनीकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे एक राष्ट्र की अदम्य वैज्ञानिक आकांक्षा का जीवंत प्रमाण है। आज जब ईरानी वैज्ञानिक जीवित न्यूरॉन्स से कम्प्यूटिंग की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक प्रौद्योगिकीय आविष्कार नहीं है, यह उस राष्ट्रीय चरित्र की अभिव्यक्ति है जिसने प्रतिकूलताओं को अवसरों में बदलना सीख लिया है।

वह प्रयोगशाला जहाँ मस्तिष्क पुनर्जीवित होता है

ते ह रा न



स्थित एक ज्ञान-आधारित कंपनी की प्रयोगशाला में रखा वह प्रोटोटाइप कोई साधारण सिलिकॉन चिप नहीं है। यह एक जैविक प्रणाली है, जिसमें हजारों जीवित मानव न्यूरॉन्स को एक विशेष माइक्रोफ्लुइडिक चिप पर संवर्धित किया गया है। विज्ञान की भाषा में, ये न्यूरॉन्स 'प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स' से विकसित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि एक सामान्य वयस्क कोशिका (जैसे त्वचा या रक्त की कोशिका) को पहले जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के जरिए भ्रूणीय अवस्था में लाया गया, और फिर उसे तंत्रिका कोशिकाओं में विकसित होने के लिए निर्देशित किया गया। यह तकनीक, जिसे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय 'ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस' या 'बायोलॉजिकल कम्प्यूटिंग' के नाम से जानता है, कम्प्यूटिंग के मूलभूत दर्शन को जड़ से चुनौती देती है। पारंपरिक कंप्यूटर जहाँ 'वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर' और बाइनरी अंकगणित (0 और 1) पर आधारित होते हैं, जो क्रमिक रूप से डेटा प्रोसेस करते हैं, वहीं यह जैविक प्रणाली मानव मस्तिष्क की तरह ही समानांतर प्रसंस्करण करती है।

डॉ. पौर-अब्बासी ने इस तकनीक की दो सबसे क्रांतिकारी विशेषताओं पर विशेष बल दिया है:

प्रसंस्करण गति में अभूतपूर्व वृद्धि: जैविक न्यूरॉन्स एक साथ हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़कर एक जटिल 3D नेटवर्क बनाते हैं, जो पैटर्न पहचान और अनुकूलन में सिलिकॉन चिप्स से कहीं अधिक तेज़ हैं।

ऊर्जा खपत में चमत्कारिक कमी: पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की तुलना में यह तकनीक दस लाख गुना तक कम ऊर्जा की खपत करती है।

इसे इस तरह समझें: मानव मस्तिष्क लगभग 20 वॉट बिजली की खपत करता है, एक सामान्य लैपटॉप से भी कम, जबकि यह प्रति सेकंड लगभग एक एक्साफ्लॉप (एक अरब-अरब गणनाएं) के समतुल्य कार्य करता है। इसकी तुलना में, दुनिया के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटर 'फ्रंटियर' को मात्र एक एक्साफ्लॉप प्रदर्शन के लिए 21 मेगावाट बिजली चाहिए, जो लगभग 10,000 घरों की बिजली खपत के बराबर है। प्रकृति ने अरबों वर्षों के विकासक्रम में जो ऊर्जा दक्षता विकसित की है, मानव निर्मित सिलिकॉन तकनीक उसके समक्ष अभी भी बौनी है।

अनुशासन बना पचास वर्षों का प्रतिबंध

ईरान की यह उपलब्धि तब और भी विस्मयकारी हो जाती है, जब हम इसे उसकी ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि में रखकर देखते हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने विभिन्न स्तरों के अंतरराष्ट्रीय और एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों का सामना किया है। अमेरिकी नेतृत्व में लगाए गए इन प्रतिबंधों ने बैंकिंग, ऊर्जा, रक्षा, परमाणु, और अंतरिक्ष सहित लगभग हर रणनीतिक क्षेत्र को पंगु बनाने का प्रयास किया।

ईरानी शोधकर्ताओं के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरणों (जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर), आवश्यक अनुसंधान सामग्री, और यहां तक कि प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुँच को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। विदेशी वैज्ञानिक सहयोग बाधित हुए और प्रतिभाशाली ईरानी छात्रों के लिए पश्चिमी विश्वविद्यालयों के द्वार संकुचित हो गए।

परिणामस्वरूप, ईरान के सामने एक मूलभूत अस्तित्वगत प्रश्न था: या तो वह वैश्विक व्यवस्था की शर्तों पर समर्पण कर दे, या फिर एक समानांतर वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करे। ईरान ने दूसरा, अधिक कठिन मार्ग चुना। आज ईरान का वैज्ञानिक परिदृश्य इस रणनीतिक निर्णय की सफलता का प्रत्यक्ष गवाह है:

कैसे AI क्रिएटिव फील्ड को निगल रहा है?

विश्व समाचार मीडिया कांग्रेस में न्यूयॉर्क टाइम्स के चेयरमैन ए.जी. सुल्जबर्गर का एक बयान अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। उन्होंने कहा है कि इतिहास की सबसे अमीर कंपनियां (AI) चोरी किए गए श्रम पर खड़ी हैं। यह टिप्पणी केवल पत्रकारिता जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी है, जहां इंसानी कल्पनाशक्ति, अनुभव और मेहनत से सामग्री तैयार होती है। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने अभूतपूर्व गति से विकास किया है। ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney और Sora जैसे प्लेटफॉर्म आज लेख लिख रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, संगीत तैयार कर रहे हैं और वीडियो भी बनाने लगे हैं। वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 2025 तक जनरेटिव AI उद्योग का आकार 60 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और अगले दशक में इसके कई गुना बढ़ने का अनुमान है। लेकिन इस तकनीकी क्रांति के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या AI रचनात्मक क्षेत्रों को नई शक्ति दे रहा है या फिर धीरे-धीरे उन्हें निगल रहा है?

AI का ईंधन आखिर आता कहां से है?

AI किसी इंसान की तरह जीवन के अनुभवों से नहीं सीखता। उसे प्रशिक्षित करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा की जरूरत होती है। यह डेटा किताबों, समाचार लेखों, शोधपत्रों, ब्लॉगों, फिल्मों, गीतों, पेंटिंग्स और इंटरनेट पर उपलब्ध अरबों दस्तावेजों से आता है। AI कंपनियां अपने मॉडल तैयार करने के लिए चार प्रमुख संसाधनों पर निर्भर हैं, प्रतिभा (Talent), कंप्यूटर चिप्स (Chips), ऊर्जा (Energy) और डेटा (Data)। इनमें से पहले तीन संसाधनों के लिए कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं, लेकिन चौथे और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी डेटा, को अक्सर बिना उचित अनुमति या भुगतान के इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह डेटा दरअसल पत्रकारों, लेखकों, संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य रचनाकारों की वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। AI उद्योग की मूल त्रुटि (Original Sin) यही है कि वह इस रचनात्मक श्रम का मूल्य चुकाए बिना उससे लाभ कमा रहा है। दुनिया की छह प्रमुख AI कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत की कुल जीडीपी से लगभग ढ़ाई गुना अधिक है। इसके बावजूद AI पर होने वाले कुल निवेश का 0.5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा उन लोगों तक पहुंचता है, जिनकी सामग्री और रचनात्मक कार्य AI को प्रशिक्षित करने में उपयोग किए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लेखक, प्रकाशक, समाचार संस्थान और कलाकार यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि उनकी सामग्री AI के लिए कच्चा माल है, तो उन्हें उसका उचित हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए?

सबसे बड़ा खतरा किसे है?

AI के विस्तार का सबसे अधिक प्रभाव उन पेशों पर पड़ रहा है, जिनकी नींव रचनात्मकता पर टिकी है। पत्रकार, लेखक, पटकथा लेखक, ग्राफिक डिजाइनर, चित्रकार, संगीतकार, फोटोग्राफर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आज सबसे अधिक असमंजस में हैं। कुछ मिनटों में AI एक लेख लिख सकता है, पोस्टर डिजाइन कर सकता है, संगीत की धुन तैयार कर सकता है या वीडियो का प्रारूप बना सकता है। कंपनियों के लिए यह समय और लागत बचाने वाला विकल्प है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह आशंका पैदा होती है कि कहीं AI मानव रचनाकारों की जगह तो नहीं ले लेगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि AI फिलहाल मौलिक सृजन नहीं कर रहा, बल्कि पहले से मौजूद सामग्री के आधार पर नए संयोजन तैयार कर रहा है। उसकी रचनात्मकता उधार ली हुई रचनात्मकता है।

क्या AI वास्तव में क्रिएटिव है?

यह सवाल आज तकनीकी और कला जगत दोनों के केंद्र में है। जब कोई लेखक उपन्यास लिखता है, कोई कवि कविता रचता है, कोई संगीतकार धुन बनाता है या कोई चित्रकार कैनवास पर रंग बिखेरता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं, सामाजिक संदर्भ और कल्पनाशक्ति होती है। AI के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। वह न दुख महसूस करता है, न प्रेम, न संघर्ष और न ही सामाजिक अनुभव। वह केवल उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर नया आउटपुट तैयार करता है। यही कारण है कि अधिकांश विशेषज्ञ AI को कलाकार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। जिस प्रकार कैमरा फोटोग्राफर की जगह नहीं ले सकता, उसी प्रकार AI भी रचनाकार की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता की चुनौती

AI की एक बड़ी समस्या विश्वसनीयता भी है। कई शोधों में पाया गया है कि AI मॉडल अक्सर गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं। तकनीकी भाषा में इसे हैलुसिनेशन कहा जाता है। पत्रकारिता में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। सुल्जबर्गर ने भी इसी ओर संकेत करते हुए कहा कि AI सार्वजनिक रिकॉर्ड से जानकारी तो जुटा सकता है, लेकिन मौलिक रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। कई अध्ययनों में पाया गया है कि AI समाचारों को प्रस्तुत करते समय तथ्यात्मक त्रुटियां करता है और कई बार समाचारों को गलत संदर्भ में पेश करता है। इसी तरह कला और साहित्य के क्षेत्र

में भी AI द्वारा तैयार सामग्री कई बार सतही, दोहरावपूर्ण और भावनात्मक गहराई से रहित दिखाई देती है। इससे सामग्री की मात्रा तो बढ़ सकती है, लेकिन गुणवत्ता की गारंटी नहीं मिलती। हर नई तकनीक के साथ यह डर जुड़ा होता है। औद्योगिक क्रांति के समय भी यही आशंका थी। कंप्यूटर आने पर भी लोगों ने रोजगार खत्म होने की बात कही थी। लेकिन इतिहास बताता है कि तकनीक पुराने कामों को बदलती है और नए अवसर भी पैदा करती है। AI के दौर में भी नए पेशे सामने आ रहे हैं जैसे AI ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI कंटेंट एडिटर, डेटा क्यूरेटर और AI ऑडिटर। इसलिए यह कहना कि AI पूरी तरह इंसानों की जगह ले लेगा, शायद जल्दबाजी होगी। भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो AI को समझेंगे और उसे अपने काम का सहयोगी बनाएंगे।

AI को रोकना न संभव है और न ही व्यावहारिक। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि रचनाकारों के अधिकार सुरक्षित रहें। जिस तरह संगीत उद्योग में कलाकारों को रॉयल्टी मिलती है, उसी तरह लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों और प्रकाशकों को भी उनकी सामग्री के उपयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए।

AI कंपनियों और कंटेंट निर्माताओं के बीच पारदर्शी लाइसेंसिंग समझौते, कॉपीराइट सुरक्षा और उचित राजस्व साझेदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।



प्रोजेक्ट गंगा से बदलेगा उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश डिजिटल क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट गंगा इसका नवीनतम उदाहरण है



डॉ. सौरभ मालवीय

प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी डिजिटल क्रांति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाना तथा ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए डिजिटल अवसर सृजित करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विगत 9 जून को लखनऊ में 'प्रोजेक्ट गंगा' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट गंगा' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'डिजिटल इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 'आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने वाली एक अभिनव पहल है। ब्रॉडबैंड आज की आवश्यकता है। इंटरनेट की स्पीड जितनी तेज होगी, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में डिजिटल उद्यमिता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए टीम यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन तथा श्री अशोक हिन्दुजा के नेतृत्व में हिन्दुजा ग्रुप का आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियोजना के पहले चरण में लाभान्वित होने वाले जनपदों के निवासियों को बधाई दी। कार्यक्रम से एमएसएमई विभाग के

फील्ड में तैनात अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व में कई चरणों में अनेक कार्य किए हैं। इनमें ई-ऑफिस की संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही, प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाना तथा कोविड कालखंड में प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीसी सखी की सुविधा जैसे उदाहरण प्रमुख हैं। इसी प्रकार 57,700 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया गया है। इनसे गांव की चुनी हुई सरकार द्वारा, गांव में ही, गांव की आवश्यकता को पूरा करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। यह सभी कार्य देश में मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में घोषणा की गई थी कि डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश सरकार आठ हजार डिजिटल उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी तथा प्रोजेक्ट गंगा इसका माध्यम बनेगा। भारतीय परम्परा में माँ गंगा की पहचान 'गंगोत्री से गंगा सागर' तक भारत की जीवनदायिनी नदी के रूप में है। माँ गंगा ने उत्तर भारत को दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि दी है, जिससे भारत दुनिया का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादित करता है। इस प्रकार माँ गंगा आत्मनिर्भर भारत व देश की एकात्मता का आधार है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह माँ गंगा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ था। ऐसे में माँ गंगा के नाम पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक सुखद अनुभूति है।

उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट गंगा' के तहत हिंदुजा ग्रुप गांवों में लास्टमाइल तक डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराएगा, जहां डिजिटल इंटरप्रेन्योर अपना कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजनाएं गांवों में लोगों को फाइनेंशियल इन्क्लूजन से जोड़ने का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री युवा योजना के अंतर्गत अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है। साथ ही 10 प्रतिशत की मार्जिन मनी की सुविधा भी दी जाती है। लगभग दो लाख युवा इस योजना के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। जनवरी 2025 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, यह एक सफल मॉडल के रूप में आगे बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट गंगा' के अंतर्गत उद्यमी का चयन तथा प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से वह अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले चरण में 'प्रोजेक्ट गंगा' के अंतर्गत प्रदेश के 21 जनपदों का चयन किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही सभी 75 जनपदों में यह सुविधा प्रारम्भ हो जाए। हम प्रदेश की सभी 350 तहसीलों, 825 विकास खंडों तथा 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप की इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद यह योजना 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिवालय की अवधारणा को नीति आयोग ने देश में एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। सरपंच की प्रक्रिया से लेकर आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने तक पहली बार ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांवों में ग्राम प्रधानों व लेखपालों को अपना कार्यालय मिल पाया है। इनके माध्यम से गांव के व्यक्ति आय, जाति, निवास व जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र गांव में ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में एक-एक पंचायत सहायक की तैनाती गई है।

उन्होंने कहा कि हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए तथा सरकार पर उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। यह विकास का एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। प्रदेश की लगभग सात हजार ग्राम पंचायतें भारत नेट से तथा कुछ निजी ऑपरेटर्स के माध्यम से ब्रॉडबैंड की सुविधा से जुड़ी हैं। आठ





हजार हजार न्याय पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाना एक चुनौती है। यदि इस चुनौती का सामना करने में सफल हुए, तो हमारे लिए ग्राम पंचायतों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचने से वह स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित हो सकेंगी। इससे अनेक सुविधाएं गांवों में दी जा सकेंगी।

हमारा प्रयास है कि 'प्रोजेक्ट गंगा' से 50 प्रतिशत महिलाएं अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएं। बीसी सखी की तर्ज पर इनकी अलग यूनिफॉर्म हो, उनके पास इससे संबंधित इक्विपमेंट हों तथा इनकी अपनी पहचान हो। मार्जिन मनी के रूप में उनका किस तरह सहयोग हो सके, जिससे वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से जुड़ सकें।

उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट गंगा' प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सफलता आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को भी साकार करती है। यह एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे गांव के लोगों को अपने उत्पादों की ऑननलाइन बिक्री का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। 'प्रोजेक्ट गंगा' भी देश में एक नया मॉडल बनेगा। प्रदेश में विभिन्न आकांक्षात्मक विकास खंडों में सीएम फैलो की तैनाती की गई है। यह सीएम फैलो वहां विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। 'प्रोजेक्ट गंगा' के कार्यों में सीएम फैलो के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए।

इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अनेक परिवर्तन हुए हैं। लोगों में यह परसेप्शन बना है कि उत्तर प्रदेश में हर कार्य संभव है। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना समय की मांग है। 'प्रोजेक्ट गंगा' के रूप में उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इस दिशा में पहल की है। यह पहल सरकार की सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में 'प्रोजेक्ट गंगा' के रूप में एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत हो रही है। यह डिजिटल क्रांति का आधार बनेगी। उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। प्रोजेक्ट गंगा' के माध्यम से यह डिजिटल विकास का भी ग्रोथ इंजन बनेगा।

यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 'प्रोजेक्ट गंगा' के माध्यम से प्रदेश के गांवों में भी शहरों की भांति डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हो रही है। एआई के युग में कृषि, सिंचाई, ऑमेटिक इक्विपमेंट जैसे कार्य ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ही संभव हैं। 'प्रोजेक्ट गंगा' शहर व गांव के मध्य की खाई को पाटेगा तथा डिजिटल डिवाइड को दूर करेगा।

हिन्दुजा ग्रुप के ग्रुप प्रेसिडेंट कॉरपोरेट अफेयर्स श्री एसके चड्ढा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक नये परिवर्तन की शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि नया उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बने। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के युवाओं को हाईटेक करने तथा महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हिन्दुजा ग्रुप प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़कर गौरवान्वित है।

होल टाइम डायरेक्टर, हिन्दुजा ग्रुप व एमडी एवं सीईओ वन ओटीटी एंटरटेनमेंट श्री वेन्स्ले फर्नांडिस ने मुख्यमंत्री जी को हिन्दुजा ग्रुप को अपने डिजिटल विजन का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी डिजिटल सुविधाओं को लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बताते हैं। तकनीक शिक्षा, हेल्थ केयर, संचार, रिमोट जॉब्स तथा मनोरंजन को आसान बनाती है। मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के नौजवानों तथा महिलाओं को डिजिटल लाइवलीहुड की दिशा में सस्टेनबल जोन्स उपलब्ध कराने का विजन है। हिन्दुजा ग्रुप ने मुख्यमंत्री जी के इस विजन पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि 'प्रोजेक्ट गंगा' उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना विकसित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार एवं उद्यमिता सृजन हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना के अंतर्गत राज्य में 20 लाख से अधिक परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा प्रथम चरण में आठ हजार से 10 हजार डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर तैयार करने का लक्ष्य है। परियोजना में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लगभग 50 प्रतिशत महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास तथा डिजिटल आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करेगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पर्यटन

काष्ठ कला केवल हस्तशिल्प नहीं,
यह **उत्तर प्रदेश** के कारीगरों के कौशल,
परंपरा और उत्कृष्ट शिल्पकला का गौरव है।

लकड़ी पर हुनर

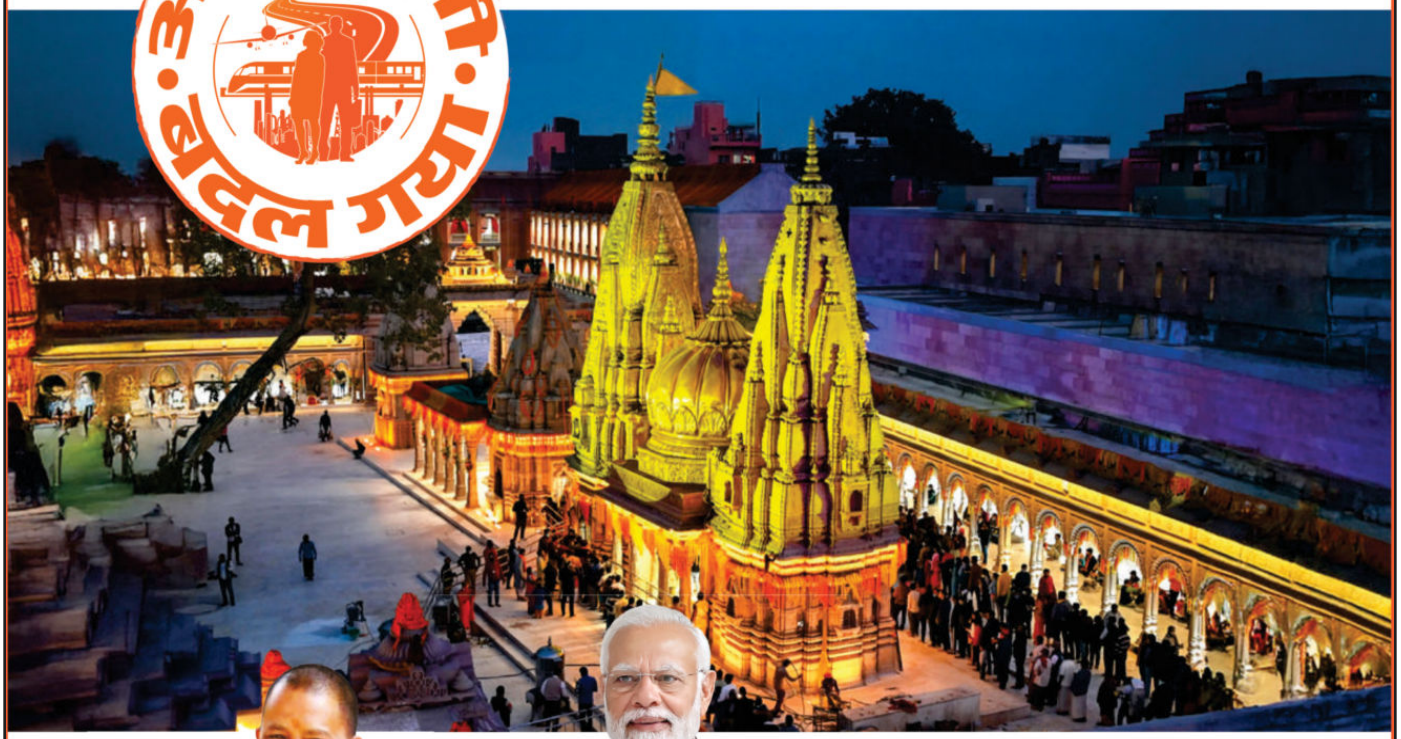
#HunarUpKa



नवनिर्माण के ९ वर्ष

पहले भय का परिवेश
आज पर्यटन प्रदेश

अपना यूपी बदल गया





2017 में
23.7 करोड़ पर्यटक

2025 में
156 करोड़+
पर्यटक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP